उत्तर प्रदेश सर्वेक्षण रिपोर्ट-2018

एडीआर द्वारा प्रस्तुत

परिचय और कार्यप्रणाली

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और आरए अस्टेरिस्क कमप्यूटिंग एण्ड डाटा सोल्यूशन प्रा.लिमिटेड (आरएएसी) ने किसी देश में संभवतः अब तक का सबसे बड़ा मतदाता सर्वेक्षण किया है। यह सर्वेक्षण पूरे भारत के 534 लोकसभा क्षेत्रों में किया गया था। इस अभ्यास में विभिन्न जनसांख्यिकी से आने वाले 2 लाख 73 हजार 487 मतदाताओं ने भाग लिया। इस सर्वेक्षण के तीन मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित की पहचान करना था: (i) मतदाताओं की प्राथमिकता पर शासन के विशिष्ट मुद्दे, (ii) उन मुद्दों पर सरकार के प्रदर्शन का मुल्यांकन, और (iii) मतदान को प्रभावित करने वाले कारक। यह सर्वेक्षण लोकसभा चुनाव 2019 से पहले, अक्टूबर 2018 और दिसंबर 2018 के बीच आयोजित किया गया था।

उत्तर प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इस रिपोर्ट में शासन के 15 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन का विश्लेषण है। मतदाताओं की यह प्राथमिकताएं उत्तरदाताओं द्वारा बताए गए मुद्दों पर सरकार के प्रदर्शन से संबंधित थी। सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के सभी 80 संसदीय क्षेत्रों में आने वाले लगभग 40,000 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया।

इस धारणा के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, सरकार से मतदाताओं की महत्वपूर्ण अपेक्षाओं को लेकर बेहतर समझ प्रदान करना और यह समझाना कि वह कैसे सरकार के प्रदर्शन का आकलन करें। इसके अलावा, यह समकालीन समय में साक्ष्य-आधारित अनुसंधान और शासन पर कार्रवाई के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को भरना चाहता है। बहुत लंबे समय तक हम पूरी तरह से विचारधारा या विभिन्न विशेषज्ञों की राय पर निर्भर रहे हैं। अब यह आवश्यक है कि हमें मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर भी विचार करना होगा। यह प्राथमिकताएं और आकलन समय के साथ बदल जाएंगे, इसलिए समय-समय पर इस तरह के सर्वेक्षण को दोहराने की आवश्यकता है।

अनुसंधान प्रारूप :

ग्रामीण, शहरी, लिंग, जाति, धर्म और आय समूहों जैसे आबादी के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आंशिक रूप से उद्देश्यपूर्ण चयन प्रक्रिया का नमूने के तौर पर उपयोग करके 18 साल की आयु से अधिक की आबादी का हर वर्ग के लिए, प्रतिनिधि नमूना चुना गया था। नमूनों को निष्पक्ष और पूरी तरह से आबादी का प्रतिनिधि बनाने के लिए हर बात का ध्यान रखा गया था। सर्वेक्षण की सटीकता 95% है, यानी, सही मूल्य सर्वेक्षण की भविष्यवाणियों के 5% के भीतर हैं।

मुख्य निष्कर्ष

- यूपी सर्वे 2018 से पता चलता है कि समग्र रूप से उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की तीन प्राथमिकताएं हैं- बेहतर रोजगार के अवसर (42.82%), बेहतर स्वास्थ्य देखभाल (34.56%) और बेहतर कानून व्यवस्था/पुलिसिंग (33.73%)।
- मतदाताओं की इन तीन प्राथमिकताओं पर सरकार के प्रदर्शन को औसत से नीचे दर्जा दिया गया था- बेहतर रोजगार के अवसर (5 के पैमाने पर 2.06), बेहतर स्वास्थ्य देखभाल (2.64) और बेहतर कानून आदेश/पुलिसिंग (2.56)।
- ग्रामीण उत्तर प्रदेश में, मतदाताओं की शीर्ष प्राथमिकताओं में कृषि ऋण उपलब्धता (44%), कृषि के लिए बिजली (44%) और बेहतर रोजगार के अवसर (39%) थे।
- ग्रामीण मतदाताओं की इन प्राथमिकताओं पर सरकार के प्रदर्शन को औसत से नीचे रखा गया था- कृषि ऋण उपलब्धता (5 के पैमाने पर 2.13), कृषि के लिए बिजली (1.94) और बेहतर रोजगार के अवसर (2.04)।
- इसके अलावा सामने आया कि सरकार ने बीज/उर्वरक (5 के पैमाने पर 1.92) और कृषि उत्पादों की उच्च मूल्य वसूली (2.15) देने में खराब प्रदर्शन किया है।
- उत्तर प्रदेश में शहरी मतदाताओं के लिए, सबसे अधिक प्राथमिकताएं थीं- बेहतर रोजगार के अवसर (49%), यातायात से फैलने वाले प्रदूषण में अधिकता (43%) और जल और वायु प्रदूषण (40%)।
- शहरी मतदाताओं की इन प्राथमिकताओं पर सरकार के प्रदर्शन को औसत से नीचे रखा गया- बेहतर रोजगार के अवसरों (2.10), यातायात से फैलने वाले प्रदूषण में अधिकता (2.10) और जल और वायु प्रदूषण (1.92)।
- यह गंभीर चिंता का विषय है कि सर्वेक्षण में सभी 31 सूचीबद्ध शासन के मुद्दों पर, सरकार के प्रदर्शन को औसत से नीचे स्तर पर रखा गया।

1. मतदाताओं की तीन शीर्ष प्राथमिकताएं और उत्तर प्रदेश में सरकार का प्रदर्शन - ग्रामीण और शहरी

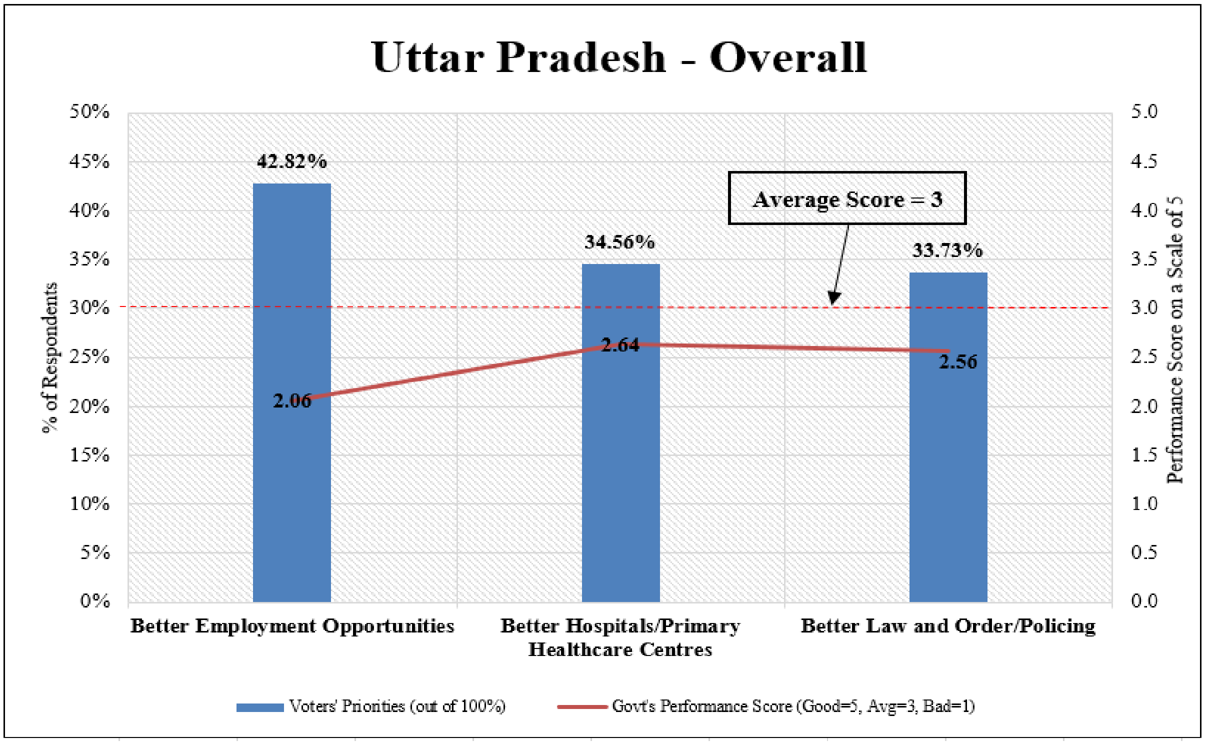

ग्राफ़ 1: उत्तर प्रदेश - मतदाताओं की शीर्ष 3 प्राथमिकताएं और सरकार के प्रदर्शनानुसार श्रेणी क्रम

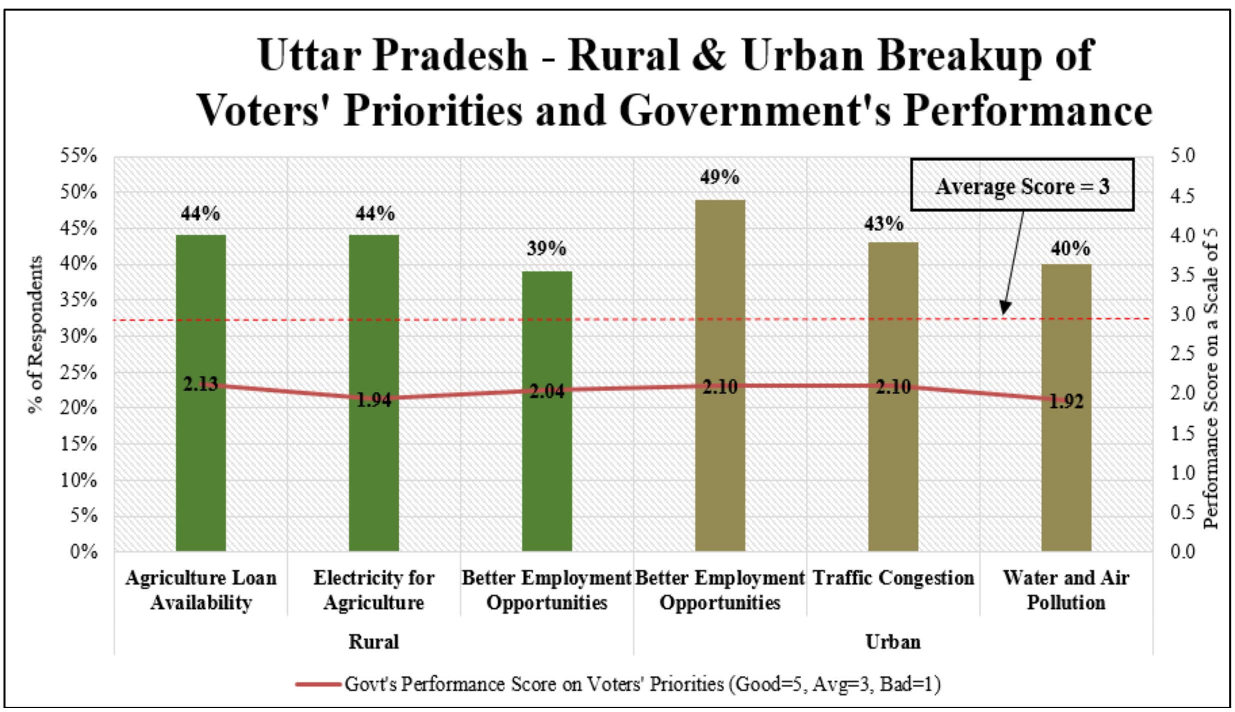

ग्राफ 2: उत्तर प्रदेश - ग्रामीण और शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताएं और सरकार का प्रदर्शन

2. ग्रामीण मतदाताओं की प्राथमिकताएं और उत्तर प्रदेश सरकार का प्रदर्शन

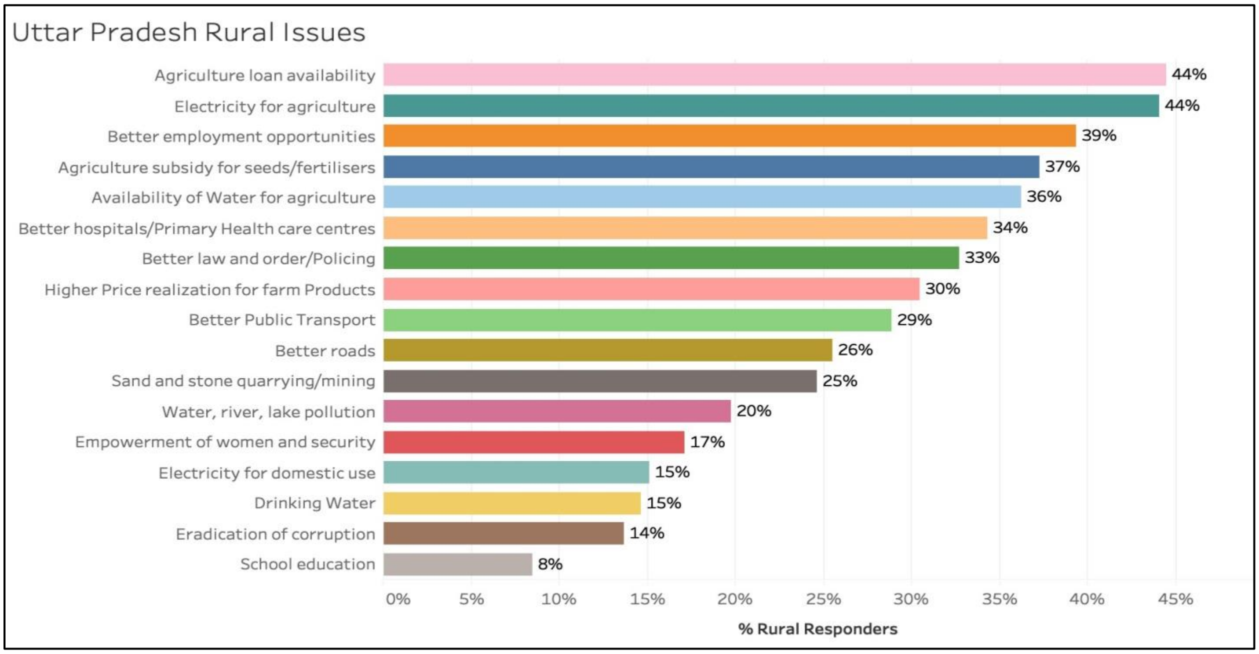

ग्राफ 3 : ग्रामीण मतदाताओं की प्राथमिकताएं

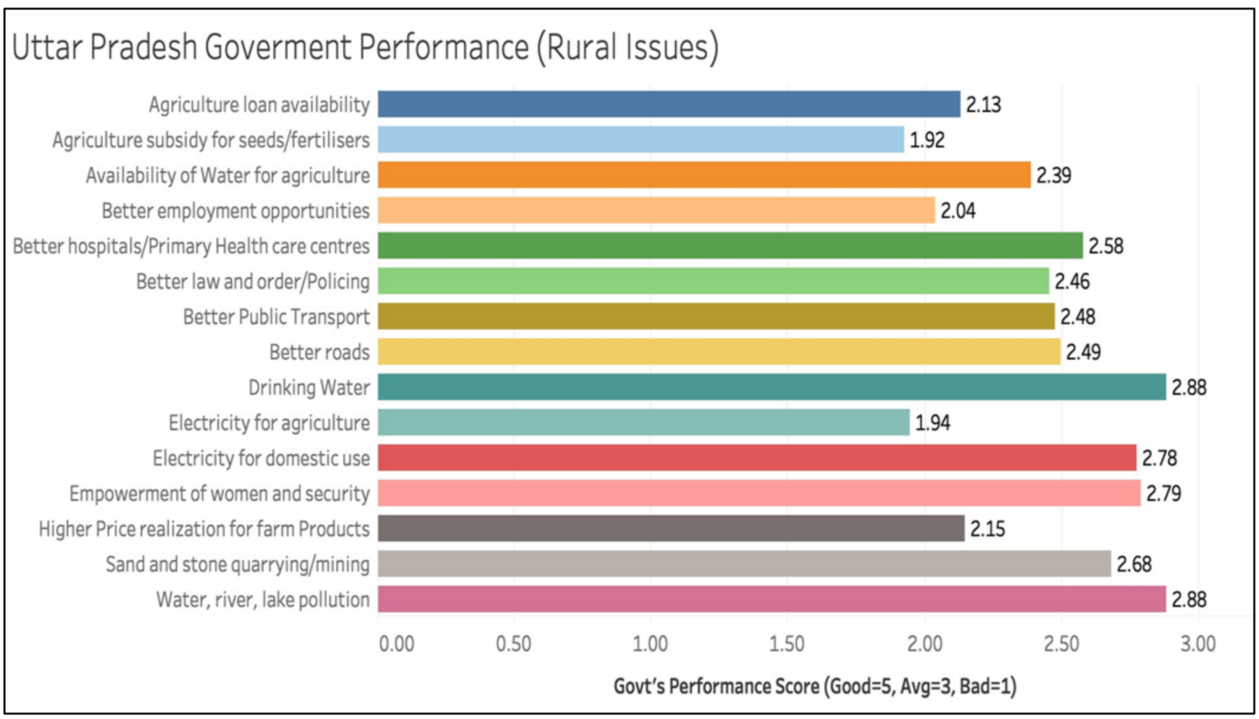

ग्राफ 4 : उत्तर प्रदेश में ग्रामीण मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर सरकार का प्रदर्शन

3. उत्तर प्रदेश में शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताएं और सरकार का प्रदर्शन

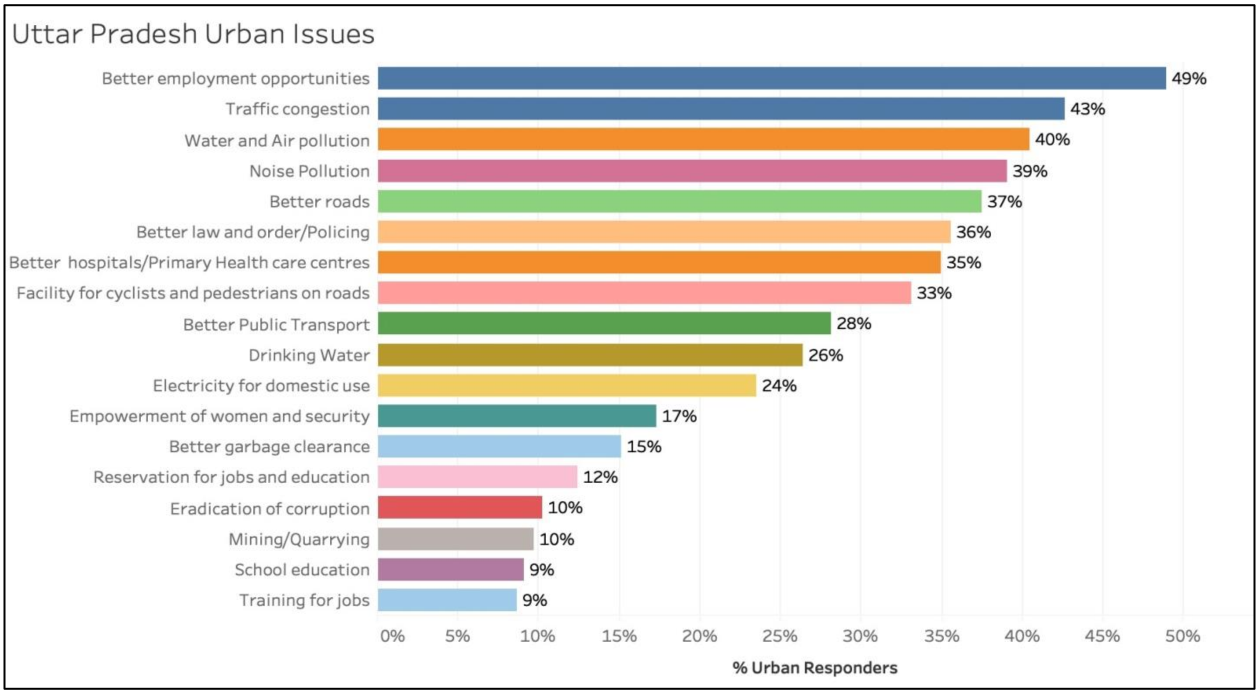

ग्राफ 5 : उत्तर प्रदेश में शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताएं

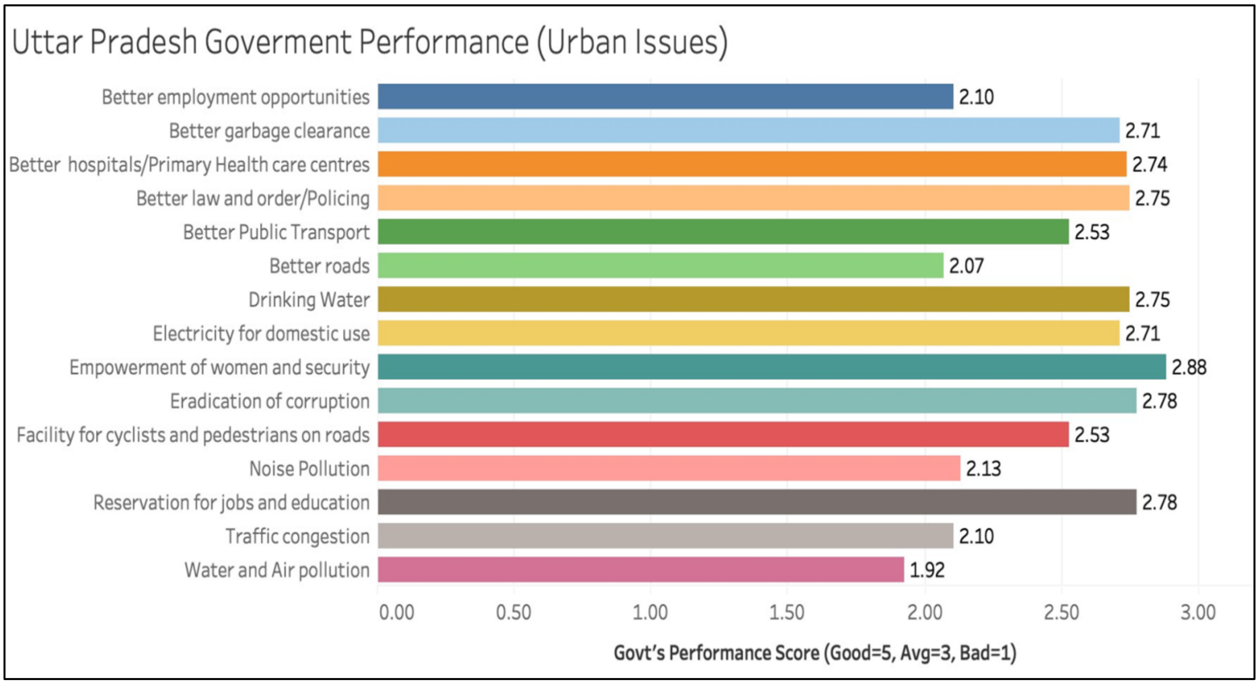

ग्राफ 6 :उत्तर प्रदेश में शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर सरकार का प्रदर्शन

मतदान का व्यवहार

- सर्वेक्षण में मतदान व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित पहलुओं का विश्लेषण करने की कोशिश की गई - (i) मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, (ii) चुनाव में आपराधिक उम्मीदवारों के बारे में राय, और (iii) अपराध और धन की भूमिका के बारे में मतदाता जागरूकता।

- मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित प्रश्न- "उम्मीदवार को वोट देने के लिए आपके क्या कारण हैं?" और "एक चुनाव में, किस उम्मीदवार को मत देना है, यह तय करते समय किसकी सलाह ज्यादा महत्व रखती है?"

- चुनाव में आपराधिक उम्मीदवारों के बारे में मतदाताओं की राय को समझने के लिए, दो प्रश्न थे- "क्या कोई आपराधिक मामले से संबंध रखने वाला संसद या विधानसभा में होना चाहिए?" और "लोग आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले उम्मीदवारों को अपना मत क्यों देते हैं?"।

- अपराध और धन की भूमिका के बारे में मतदाता जागरूकता का आकलन करने के लिए, निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए थे- "क्या आप जानते हैं कि नकद/धन/उपहार आदि का वितरण अवैध है?", क्या आप पिछले चुनाव के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र में नकदी/धन/उपहार/ शराब के वितरण के उदाहरणों से अवगत हैं? " और "क्या आप जानते हैं कि आप उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं?"।

उत्तर प्रदेश में मतदान व्यवहार पर प्रमुख अवलोकन

- यूपी सर्वेक्षण 2018 के अनुसार, सबसे अधिक मतदाताओं ने कहा कि चुनाव में मतदान करने के लिए सीएम उम्मीदवार सबसे महत्वपूर्ण कारण (महत्वपूर्ण: 43% और बहुत महत्वपूर्ण: 42%) था। इसके बाद मतदान के लिए दूसरा कारण उम्मीदवार की पार्टी(महत्वपूर्ण: 52% और बहुत महत्वपूर्ण: 27%) और तीसरा कारण उम्मीदवार स्वयं (महत्वपूर्ण: 59% और बहुत महत्वपूर्ण: 16%) था।

- चुनाव में किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने के पीछे 15% मतदाताओं के लिए नकद, शराब, उपहार आदि का वितरण एक महत्वपूर्ण (10%) और बहुत महत्वपूर्ण (5%) कारक था।
- यूपी के 86% मतदाताओं ने कहा कि चुनाव में किस उम्मीदवार को वोट देना है, यह तय करने के लिए उनकी अपनी राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद, 5% मतदाताओं ने कहा कि उनके लिए अपने पति या पत्नी की राय और 5% मतदाताओं ने परिवार के सदस्यों की राय को सबसे अधिक महत्व दिया।

- बड़ी संख्या में 74% मतदाता जानते थे कि नकदी, उपहार आदि का वितरण अवैध है।
- 30% मतदाताओं ने कहा कि उनके पास ऐसे उदाहरणों हैं जहाँ मतदाताओं को उनके वोट के बदले कोई प्रलोभन दिया गया।
- 98% मतदाताओं ने व्यक्त किया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार संसद या विधानसभा चुनाव में नहीं होने चाहिए।
- मात्र 35% मतदाता जानते थे कि वह उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- आपराधिक प्रत्याशिओं को मतदान करने के संबंध में 36% मतदाताओं का अनुभव था कि उम्मीदवार अन्यथा अच्छा काम करता है।
- आपराधिक दर्जे वाले उम्मीदवारों को चुनने में 36% मतदाताओं के लिए जाति और धार्मिक विचार भी प्रमुख कारक हैं।
- आपराधिक उम्मीदवारों के लिए मतदान में एक और बड़ा कारक (35%) था कि प्रत्याशी शक्तिशाली है और क्योंकि मतदाता आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानते हैं।

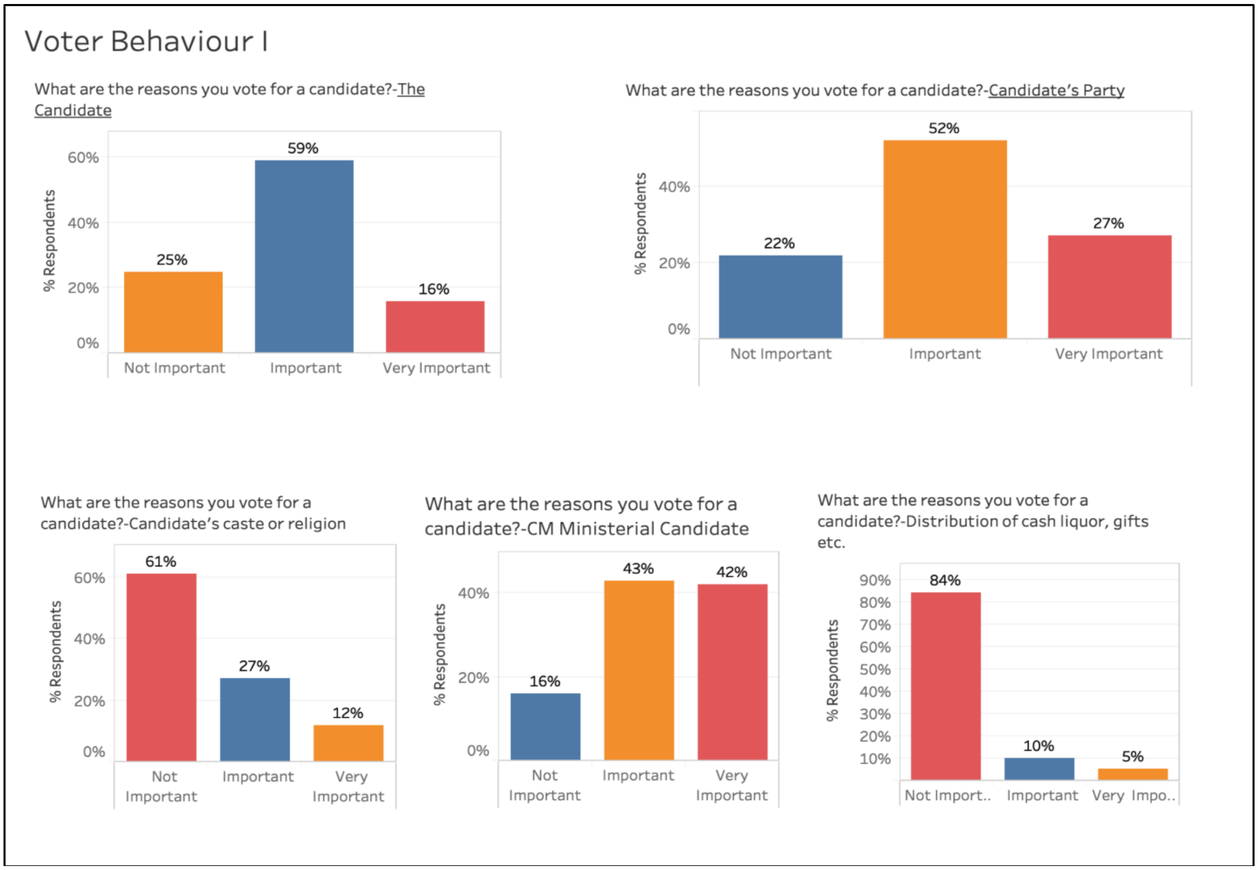

ग्राफ 7 :मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक

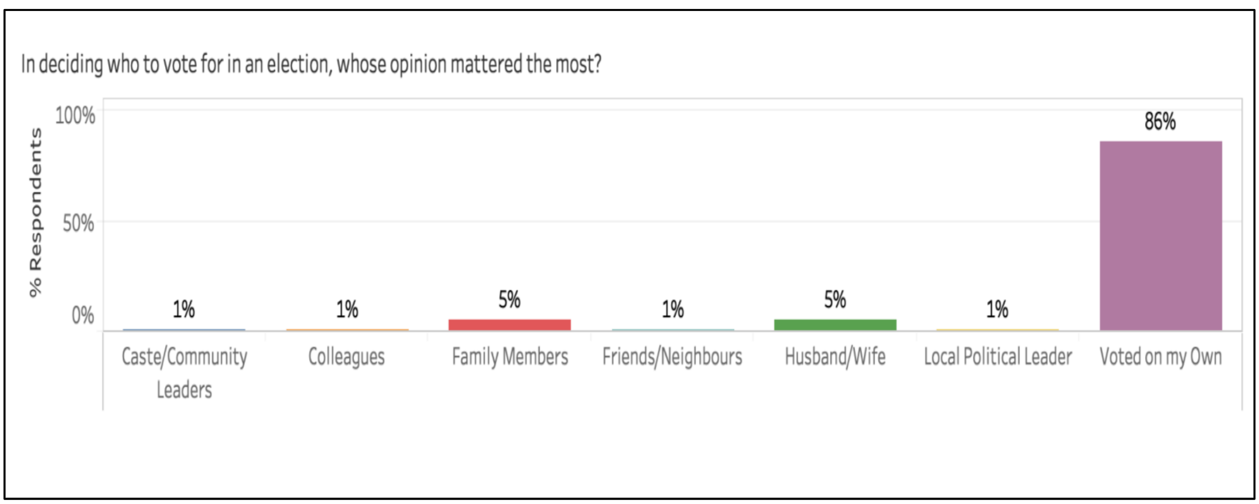

ग्राफ 8 :चुनाव में किस प्रत्याशी को मतदान करना है, यह तय करने में किसकी सोच ज्यादा महत्वपूर्ण है

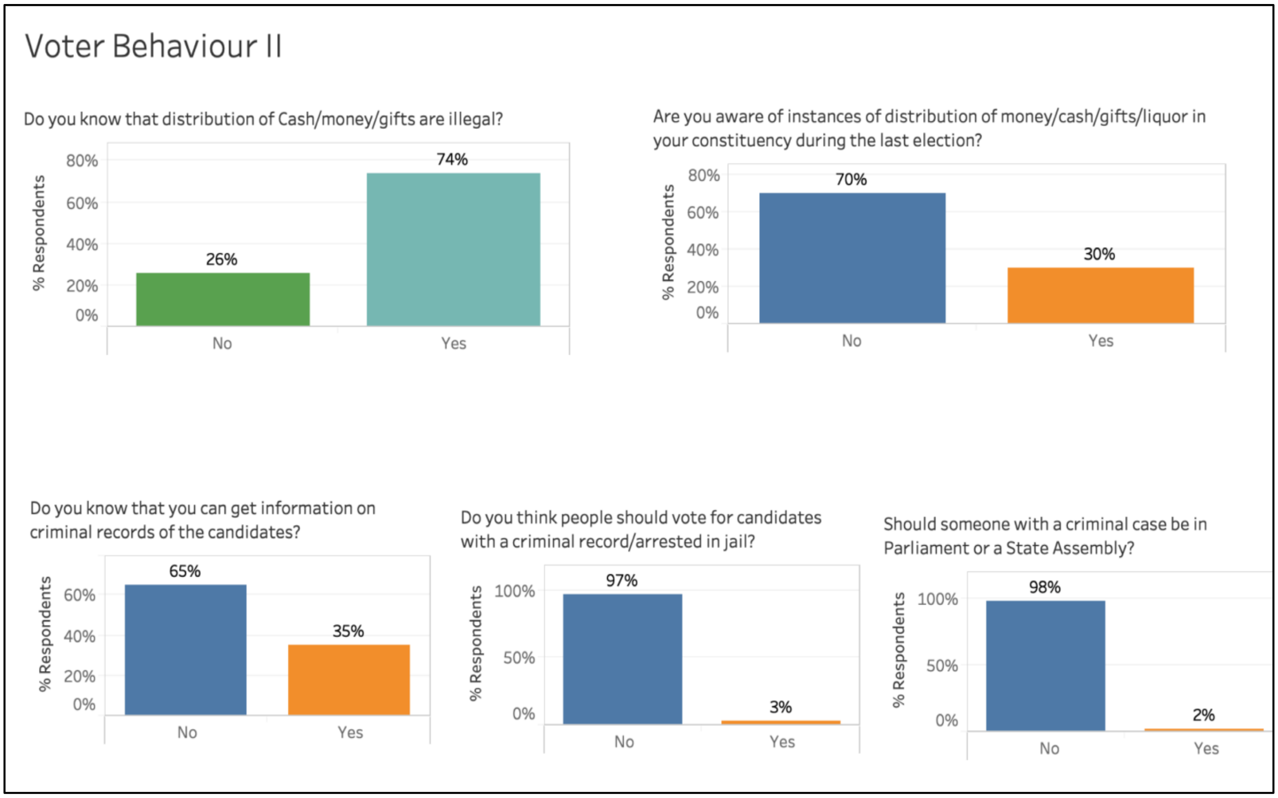

ग्राफ 9 :चुनाव में अपराध और धन की भूमिका के संदर्भ में मतदाता जागरुकता

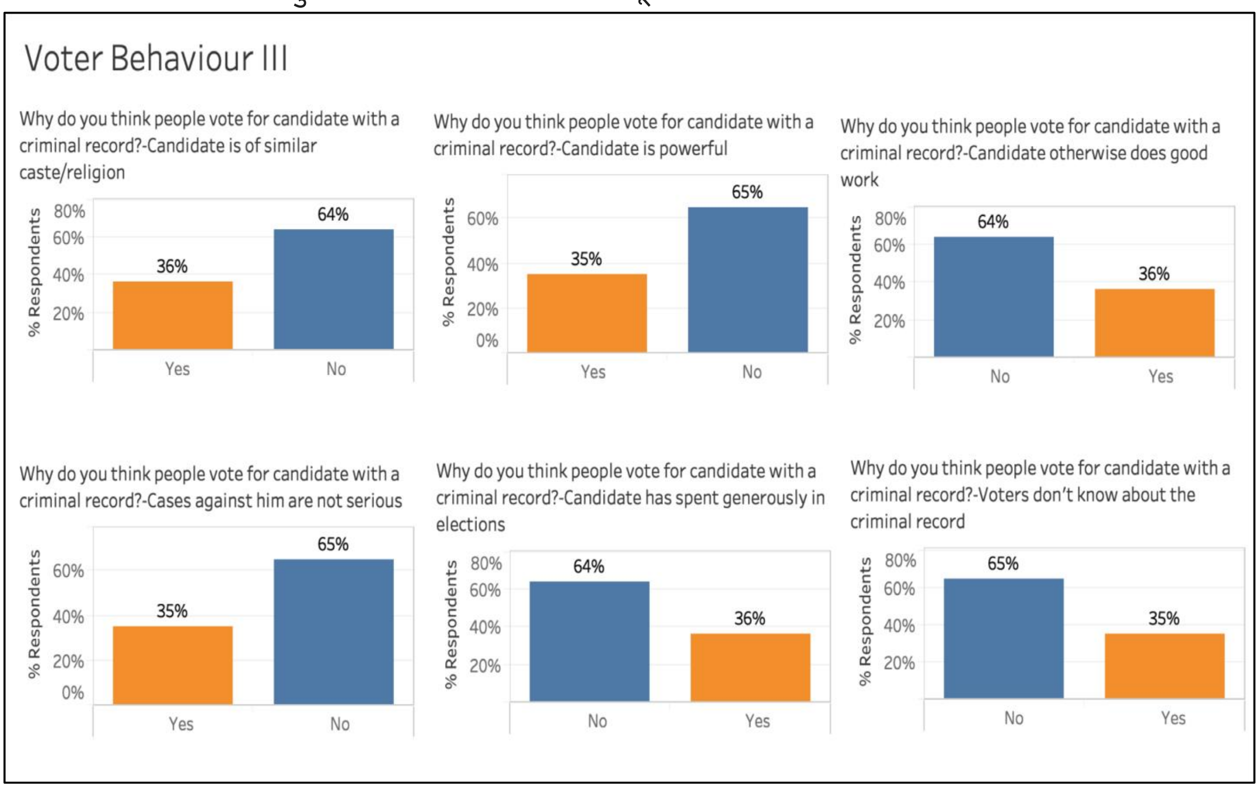

ग्राफ 10 :चुनाव में आपराधिक उम्मीदवारों से संबंधित मतदाताओं के विचार

मतदाता का जनसांख्यिकीय विवरण

- सर्वेक्षण में 69% मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों से और 31% शहरी क्षेत्रों से थे।
- 61% परुष और 39% महिलाएं थी।
- 73% सामान्य, 7% पिछड़ा, 20% हरिजन वर्ग से थे।

अन्य प्रतिवादी विवरण नीचे दिए गए ग्राफ़ से देखे जा सकते हैं।

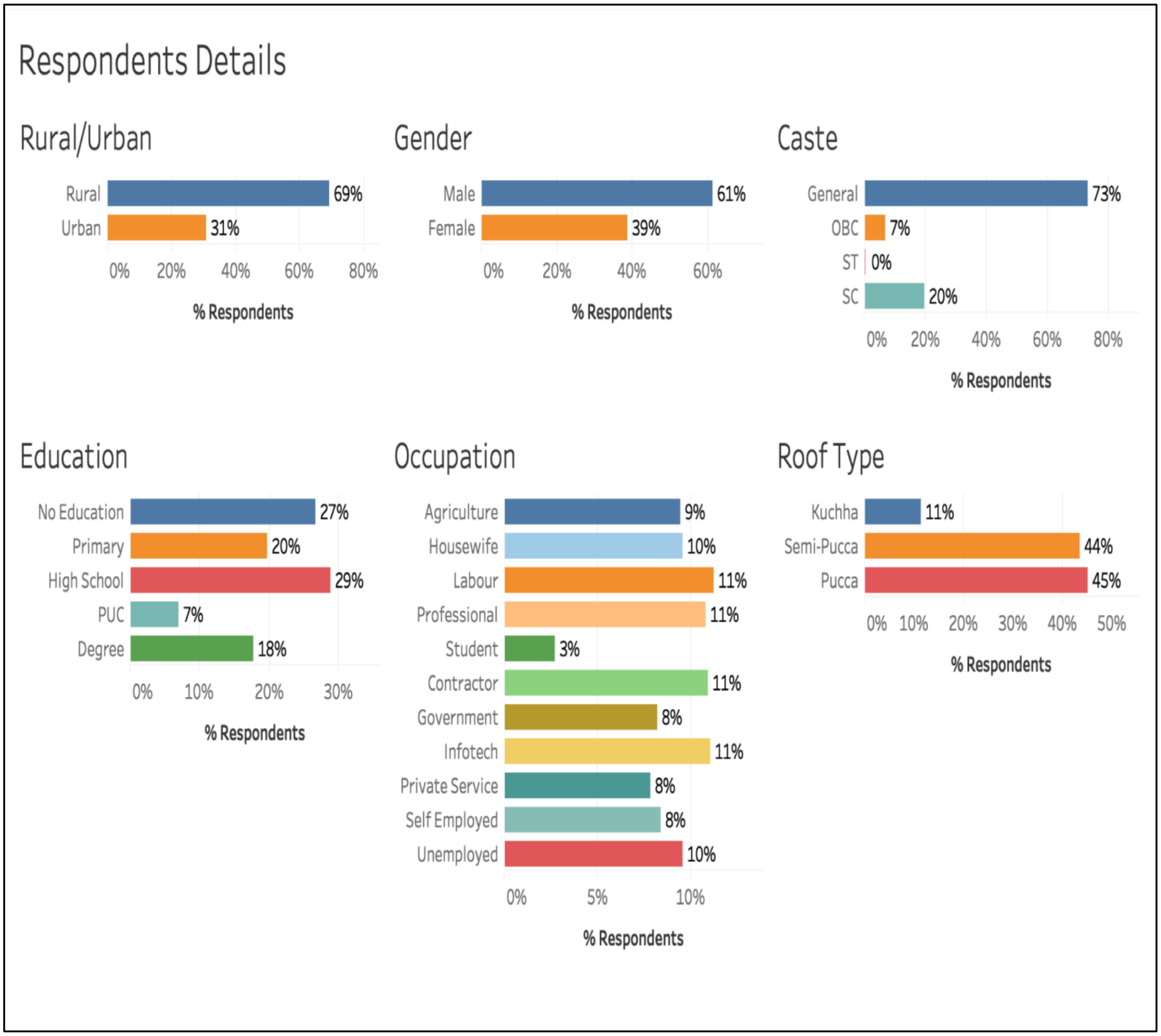

ग्राफ 11 :मतदाता जनसांख्यिकीय विवरण

निष्कर्ष

उ.प्र. सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की प्राथमिकताएं सत्ताधारी सरकार द्वारा उपेक्षित रही हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार ने सभी सूचीबद्ध शासन के मुद्दों पर खराब और कमतर प्रदर्शन किया है। मतदाताओं की प्राथमिकताओं और उत्तर प्रदेश में सरकार के प्रदर्शन की प्रवृत्ति के विश्लेषण में सरकार और विधायकों पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं।

- बुनियादी ढाँचे, सामाजिक और आर्थिक विकास आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक नीतियों से संबंधित निर्णय पूरे समाज कल्याण की कीमत पर समाज के कुछ वर्गों के पक्ष में बने हैं?
- क्या सरकार के बजट व्यय को मतदाताओं की प्राथमिकताओं के अनुसार पुनःनिर्दिष्ट/योजना बनाने की आवश्यकता है?
- घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में राजनीतिक दलों को कैसे अधिक जवाबदेह बनाया जा सकता है?
- समाज के वंचित वर्गों को रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किन नीतिगत बदलावों की आवश्यकता है?

यह तथ्य है कि राजनेता चुने जाने के बाद मतदाता की कोई भूमिका नहीं होती है, निर्वाचित उम्मीदवारों की प्राथमिकता राजनीतिक दलों द्वारा निर्धारित की जाती है। तब यह आशा की जाती है कि मतदाता प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बेहतर राजनीतिज्ञ का चुनाव करता है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है राजनीति और शासन में मौजूद घटकों को प्राथमिकता देना। इस श्रेणी निर्धारण के पीछे वास्तविकता है जिसका हमारे देश में रहने वाले लोग प्रतिदिन सामना करते हैं। सर्वेक्षण में निकले यह परिणाम हमारी सरकार और नेताओं को आंकड़ों के पीछे की सच्चाई को बताने में सहायक होंगे।

अस्वीकृति

यह सर्वेक्षण सबसे अधिक प्राथमिकता वाले प्रशासन के मुद्दों का पता लगाने के लिए आयोजित किया गया था जो भारत के मतदाता अपने दैनिक जीवन को प्रभावित करने के लिए देखते हैं। इसमें यह भी जांचा गया कि मतदाता उन मुद्दों के समाधान को लेकर सरकारों से खुश हैं या नहीं।

उन्होंने वैज्ञानिक ध्वनि तकनीकों का उपयोग करके सर्वेक्षण किया था और परिणामी निष्कर्षों और रिपोर्टों को तैयार करने के लिए मान्यता प्राप्त डेटा विश्लेषण तकनीकों का उपयोग किया था। इस रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्ष भारतीय मतदाताओं द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।

यह सर्वेक्षण भारत के मतदाताओं की शासन से मांग और संबंधित सरकारों द्वारा भारतीय मतदाताओं को दी गई सेवाओं के बीच की खाई का अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रयास है। इस सर्वेक्षण द्वारा किसी भी सरकार या राजनीतिक दल या व्यक्ति या किसी अन्य संगठन की सराहना या आलोचना करने का प्रयास नहीं किया गया।

इस रिपोर्ट में निहित डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एडीआर द्वारा हर संभव प्रयास किया गया है।

इस रिपोर्ट का उपयोग या प्रस्तुत करने वाले किसी व्यक्ति को 'उत्तर प्रदेश सर्वेक्षण रिपोर्ट - 2018' के रूप में इसे स्त्रोत स्वीकार करना चाहिए।

To Get Information About Candidates/Parties/MPs/MLAs/ Corporators/PILs in courts

National Election Watch

Give us missed call on: **08010445555**

Toll Free Helpline No: **1800-110-440**

Journalist Helpline no: **8010394248**

Subscribe to ADR on **WhatsApp** for updates: **7840067840**

Visit: **www.myneta.info**

Email: **adr@adrindia.org**

Send SMS: **Myneta <pincode or constituency> to 56070 or 9212356070**

To contact ADR State Partners, visit:
https://adrindia.org/about-adr/state-coordinators

Social Media

/myneta.info /adrindia.org @adrspeaks /adrspeaks /adrspeaks

https://in.linkedin.com/company/association-of-democratic-reforms-adr-

Our Websites

www.adrindia.org

Provides detailed analytical reports of Lok Sabha, State Assemblies, local body elections & financial reports of political parties & ongoing PILs in courts

www.myneta.info

Provides full information of criminal cases, asset, liability and education details declared by candidates in the self sworn affidavits

Android Apps

Myneta: The criminal, financial, educational & other background information self declared by candidates in their affidavits during elections is now available on your mobile phones.

Election Watch Reporter: This app provides a tool to the citizens to capture violations of election related laws & the code of conduct.
Both the applications are available on Google Play Store.